REFERENCE TO THE DISCRIMINATION AGAIST THE USE OF HINDI

श्री कैलाश पति मिश्र (बिहार) : सभापति महोदय, देश 1947 में आजाद हुआ । आजादी के साथ कई पहलू लगे हुए हैं और देश के स्वाभिमान के साथ अपनी भाषा, भारतीय भाषायें भी लगी हुई हैं । समाचार समितियों के क्षेत्र में पहले मात्र अंग्रेजी का प्रभाव था और इस क्षेत्र में कोई भी भारतीय भाषा उपस्थित नहीं थी । 1949 में एक हिन्दी समाचार समिति की स्थापना हुई, हिन्दुस्तान समाचार के नाम से और 1966 में एक दूसरी समाचार समिति, समाचार भारतीय की स्थापना हुई । 1973 तक अपनी गति से ये समाचार समितियां बढ़ती रही लेकिन 1976 में केन्द्रीय सरकार ने दोनों अंग्रेजी समाचार समितियां और दोनों हिन्दी समाचार समितियों की एक खिचड़ी बनाकर एक समाचार समिति बना दी और उसका नाम रख दिया समाचार । बाद में सरकार बदली और जनता राज में फिर से चारों समितियों को अलग अलग काम करने का मौका दिया गया । हिन्दुस्तान समाचार एक सहकारी संस्था थी और समाचार भारतीय एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम कर रही थी । दुर्भाग्य यह कि फिर कांग्रेस की सरकार आई और उसने सबसे पहले हथौड़ा इन हिन्दी समाचार समितियों पर चलाना शुरू किया । जब सेवा शुल्क...

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : इसकी जनता सरकार ने तोड़ा . (**व्यवधान**)

श्री कैलाश पति मिश्र : आपको बोलना है तो बाद में बोलिये ।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं ।

श्री कैलाश पति मिश्र : मैं यही कह रहा था जो आप कह रहे हैं लेकिन अलग अलग करने पर भी इन समाचार समितियों को विकसित करने का अवसर जनता सरकार ने दिया था । लेकिन आपने आने के बाद क्या किया ? महोदय, पी० टी० आई० और यू० एन० आई० को सेवा शुल्क 1 करोड़ के लगभग दिया जाता है लेकिन हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को मात्र 10 लाख दिया जाता है । इसके बाद 1982 से 1985 तक आपने क्या किया । यह हवाला दे कर कि थोड़ा सा घाटा लग रहा है, हिन्दुस्तान समाचार समिति का 6–7 लाख का घाटा था, आपने दिल्ली के रजिस्ट्रार के माध्यम से उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और तीन साल तक रखा । तीन साल के अन्तर्गत 6–7 लाख का घाटा बढ़ कर के 75 लाख के ऊपर पहुंच गया । आज यह स्थिति है कि आपने पूर्णतया सेवा शुल्क इन हिन्दी समाचार समितियों का दोनों को ले कर समाप्त कर दिया । हालत यह हो गई है कि तीन सौ कर्मचारी जो 18–18, 20–20 और 25–25 साल से काम करते रहे हैं अनुभवी पत्रकार हैं वे सड़कों पर घूम रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। आज उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है । मंत्रालय के मंत्री महोदय माननीय गाडगिल जी ने कई बार संकेत दिया परन्तु आज तक उन पत्रकारों को किसी ने देखरेख नहीं की । 1982 से 1985 तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन रहा यहां तक कि उनका प्रोविडेंट फण्ड का पैसा भी नहीं दिया, ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया । एक एक पत्रकार ऐसा है जिसका एक एक लाख रुपया पड़ा हुआ है । उनकी भी चिंता नहीं की जा रही हैं ।

[उप सभापति महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, 38 साल की आजादी के बाद भारतीय भाषा में प्रवीण बने हुए पत्रकार जो सड़कों पर घूम रहे हैं, भूखों मर रहे हैं मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक और कोई दूसरी स्थिति नहीं हो सकती है । मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार जवाब दे हिन्दी समाचार समितियों की हत्या तो कर ही दी लगता है अब यह जिन्दा नहीं हो सकेंगी लेकिन आप इन पत्रकारों की हत्या न होने दें इनको भूखों नहीं मरने दें इनका कहीं

न कहीं समायोजन करें इनको स्थान दें। इसके लिए सरकार को विवश करना चाहिये। सरकार इस उत्तर को लेकर के आ जाए। महोदय, हिन्दी का कितना उत्थान हो रहा है मैं किसी के ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहता हूं। अगर कोई मित्र हिन्दी में नहीं अंग्रेजी में काम करना चाहते हैं तो मैं उनके ऊपर हिन्दी नहीं लादना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले एक उत्तर दिया गया कि स्टेट बैंक की मेरठ जिले में स्कौटी ठांडा शाखा में से जिन लोगों ने सुरेन्द्र कुमार को निकाला उन्हीं के हाथ इन्क्वायरी दी जाती है और इक्वायरी में अनुशासन-हीनता का आरोप लगा कर जवाब दिया जाता है। मैंने पूछा था कि आपकी मेरठ की इस स्कौटी ठांडा शाखा जिसको हिन्दी चयनिक शाखा घोषित किया उसके बाद सुरेन्द्र कुमार ने हिन्दी में काम करना शुरू किया। मैं कहना चाहता हूं कि अकेले उसने काम करना शुरू किया। अगर जांच करनी थी तो सीधा रास्ता था उस में से और कितने कर्मचारियों ने हिन्दी में काम करना शुरू किया। महोदय जब हिन्दी में उसने काम करना शुरू किया तो उसे बुला कर के डांटा गया। तब उसने कहा कि सरकार का सर्कुलर है एक परि-पत्र है और बैंक के प्रबन्धक कहते हैं कि वह तो फाइल में रखने के लिए है काम करने के लिए नहीं है। उसने कहा कि आप लिख करके आदेश दीजिए। यह उसकी अनुशासनहीनता माना गया। उसकी पत्नी पागल हो गई है और मुझे एक यह खबर मिली है कि शायद उसके ससुर को भी हार्ट अटैक हो गया वह भी सम्भवत: जिन्दा नहीं है। इतनी बड़ी घटना होती चले, इतना बड़ा अन्याय होता चले जिन लोगों ने उसको सताया यहां उन्हीं की अनुशंसा ले कर यह जवाब दिया गया यह ठीक नहीं है इसकी जांच होनी चाहिये। आई.आई.टी. का पहले सवाल उठाया श्याम नन्दन पाटक का साथ अन्य मित्रों ने दिया, सत्तारूढ़ दल के मित्रों ने भी साथ दिया उस समय वह बच गया लेकिन आज भी आई.आई.टी. की हालत यह है कि हिन्दी में काम करने के बाद जो वहां का निर्देशक है प्रिंसिपल है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिये। दूसरा एक विद्यार्थी अमरेन्द्र कुमार सिन्हा था आई.आई.टी. में जो संकट में फंसा इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हिन्दी में काम करने वाले हिन्दी की प्रगति में रुचि रखने वाले किसी के शिकार न बनें नौकरी के शिकार न बनें उनका जीवन बरबाद न हो। इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे। हिन्दी किसी के ऊपर थोपने का सवाल नहीं है।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, I also support the Special Mention which has been made by hon. friend. In the "Hindustan Samachar" and "Samachar Bharati" there are about 270 employees, including very talented Journalists, working there. They should end this discrimination. Even PTI wanted to have a written test in Hindi for the Journalists. I suggest that the Government should take immediate steps to end this discrimination and provide them employment.

SHRI L. K. ADVANI (Madhya Pradesh): We associate ourselves with him.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): We associate ourselves with him.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): माननीय सदस्य श्री कैलाशपति मिश्र जी ने जो प्रश्न भारतीय समाचार, हिन्दुस्तान समाचार के लिए उठाया है सचमुच में मैं उनकी इस बात का समर्थन करते हुए उसमें यह जोडना चाहता हूं कि भारत सरकार सचमुच में जो संविधान की भाषा राजभाषा हिंदी है उस राजभाषा हिंदी को 22 वर्ष तक राजभाषा अधिनियम के पारित होने के बाद 17 वर्ष तक राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के बाद भी इस मंत्रालय में जो एक स्वतंत्र भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की संस्था थी उसको हटाकर हिन्दी को अनुवाद की भाषा बनाकर रखना चाहते हैं क्या ? आज भी कांग्रेस का बहुमत है। अगर कांग्रेस को यह लगे कि सचमुच में देश के लिए स्वाभिमान को और अपनी भाषा के बोलने के लिए उनको उस गुलामी को छोड़ने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मो हो रहा है तो संविधान में परिवर्तन ला सकती है

है । लेकिन जब तक संविधान में यह धारा मौजूद है कि देश की राजभाषा हिंदी है और जो सर्वसम्मत भाषा मानी गयी है तब तक भारत सरकार उसके अनुकूल चलने के लिए बाध्य है । आज भी वित्त मंत्री महोदय जी ने जो सवाल का जवाब दिया, मैं पहले भी उनसे कह चुका हूं कि आपके मंत्रालय के वित्त सचिव राजभाषा अधिनियम को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वार्षिक कार्यक्रम पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर वह कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा गया है कि एक अनुभाग में हिंदी में मूल में सब काम किया जाये मैंने उन्हें पुस्तक देकर 10 पृष्ठ के "च" में दिखाया कि यह लिखा हुआ है कि हिंदी अनुभाग को छोड़कर एक अनुभाग अवश्य हिन्दी में सब कार्य करे । लेकिन आज तक यह बात नहीं हो रही है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सचमुच में भारत सरकार राजभाषा हिंदी को जो संविधान की भाषा है उसे अनुवाद की भाषा बनाकर रखना चाहती है क्या ? श्रीमन, मैंने गाडगिल जी के सामने भी प्रश्न उपस्थित किया था कि एक षड्यंत्र हो रहा है, पी. टी. आई., यू. एन. आई. यू. पी. आई., आदि के मेल से इनके कर्णधारी के मेल में कि हिंदी की जो प्रभुसत्ता है उसको समाप्त करें। आपने बुलाया भी किससे राय लेने के लिए जो पी. टी. आई. के अध्यक्ष है उससे राय लेने के लिए ? पी.टी. आई., जो अंग्रेजी संस्था है, यह राय देंगे कि हिंदी समाचार संस्था चलती रहे । मैं एक बात मान लूंगा कि हिंदी की दोनों संस्थाएं चलने लायक नहीं थी लेकिन अगर देश में एक बार स्विच ओवर करें कि देश की राजभाषा हिंदी होगी तो हिंदी में ही सभी काम होगा किसी दूसरी भाषा में नहीं । मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि इंग्लैंड में वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं थी लेकिन जब उनका स्वाभिमान जागा तो एक दिन में ही स्विच ओवर हो कर अंग्रेजी राजभाषा हो गयी । जिस दिन यहां की राजभाषा भी हिन्दी हो जायेगी तो भारत सरकार को और देश को आवश्यकता पड़ेगी कि हिंदी में ही समाचार संस्था वितरण करे। आज भी आवश्यकता है कि हिंदी समाचार संस्था चले। नहीं चलने लायक है तो नहीं चलाएंगे जबकि आवश्यकता है ? जब पी० टी० आई० और यू० एन० आई० सभी को भारत सरकार मदद करती है तभी वे इतनी समर्थ संस्थाएं हो पाती हैं । तो भारतीय भाषा को भारतीय स्वाभिमान की भाषा को क्यों नहीं चलाया जाये । श्रीमन्, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि रोज पढ़ता हूं कि आज हिंदी पारितोषिक मिला । अभी राष्ट्रपति महोदय जी ने हिंदी में अधिक काम करने वालों को पारितोषिक वितरित किये । गृह मंत्री जी ने भी अधिक काम करने वालों को अभिभाषण दिया लेकिन जो सचमुच काम करने वाले हैं वे सताये जाते हैं अपमानित किये जाते हैं और नौकरी से हटा दिये जाते हैं। एक दो कांड नहीं हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय हों या गृह मंत्री महोदय हों, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सचमुच में नौकरशाही देश को चला रही है और नौकरशाही की सुरक्षा इसमें है कि अंग्रेजी देश में बनी रहे और अंग्रेजी भाषा के बने रहने के कारण ही उनके बाल बच्चों की जिंदगी ठीक रहेगी । इसीलिए डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भाषा की नीति एक करें, पढ़ाई की भाषा एक करें, एक तरह की भाषा करें । लेकिन उसका निश्चित रूप से पालन नहीं हो रहा है । श्रीमन, राजभाषा को सबसे बड़ी एक और कठिनाई है । मैं एक तकनीकी बात कहना चाहता हूं कि जो कि छूट गयी है । यांत्रिक सुविधायें जब तक राजभाषा को नहीं मिलती हैं यांत्रिक सुविधाओं से मेरा अर्थ है, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स, कम्प्यूटर की सुविधा, ये सब संसाधन, इलेक्ट्रिकल टंकण मशीन ऐसी 13–14 प्रकार की सुविधायें हैं । और आज मंत्रालय विभाग द्वारा ये सुविधायें प्राप्त नहीं करायी जा रही है । भारतमें सरकार कम्प्यूटर पर बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाई करा रही है । यही बच्चे जब दस वर्ष बाद काम करने के लिए जायेंगे तो कहेंगे कि हमें तो अंग्रेजी में शिक्षा दी है और आज आप हिन्दी में काम करने के लिए कहते हो ? तो यह सब कैसे होगा ? इसी प्रकार शिक्षा नीति में भी

आवश्यकता है कि हम यांत्रिक सुविधाएं उसको प्रदान करें । (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Rajya Sabha) (SHRII SITARAM KESARI): Sir, how long will you allow him?

श्री उपसभापति आपने ज्यादा समय ले लिया है । . . . . (व्यवधान)

SHRI SITARAM KESARI: Sir, Special Mention does not mean he can make a speech. You must ring the bell now, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yadav, you were only allowed to associate yourself with the issue. So, it is not fair in your part to make a speech on this. I hope you will finish soon. I will have to call Mr. Birla now to make his Special Mention.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ दो-एक शब्द कह कर ही अपनी बात समाप्त करूंगा । ये ऐसे मौलिक सवाल हैं जिनको हमेशा नहीं उठाया जाता है । आज भी हाउस में प्रश्नकाल के दौरान ऐसा मौलिक सवाल उठाया गया और वह मौलिक सवाल का हम जवाब चाहते हैं । अब सवाल यह है कि भारत सरकार को यह जो सवाल किए जाते हैं उनके जवाब भी ठीक से नहीं मिलते हैं । राजभाषा के सवाल के उत्तर रख देने की बात तो कम से कम हो । इसीलिए हम चाहते हैं और हमने प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है कि जब आप विदेश में जाते हैं, वहां जाकर जैसे वहां के राष्ट्र अपनी भाषा में बोलते हैं वैसे ही आप भी अपनी भाषा में बोलिये ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If it is such an issue, than you raise it separately, but not now. You conclude now, please.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । भारत के मंत्री, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति अगर किसी विदेश से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर राजभाषा में बात करें जिससे राजभाषा का गौरव बढ़ेगा और तभी इसका प्रचार-प्रसार भी होगा ।

SHRI S. W. DHABE: Sir, the Minister must be called upon to make a statement on this. You should ask him to make a statement on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have already spoken.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, this is a very serious matter. Why are they keeping quiet?

REFERENCE TO THE DEAL FOR THE PURCHASE OF "HERMES" AIRCRAFT CARRIER FROM THE U.K.

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Sir, India and Britain are on the verge of finalising a deal worth about sixty million pounds for buying an ancient British aircraft carrier, "Hermes". Sir, it is very surprising that we are going in for this obsolete aircraft carrier and I do not know why India wants to buy so much of junk from the United Kingdom. We are already committed to the Westland halicopter deal and now we are going in for the "Hermes" aircraft carrier. This aircraft carrier, "Hermes", was built in 1944 and is continued to be built in 1954. It was last used during the Falklands war and, after that, it has been lying in one of the ports of the United Kingdom. With its boilers unserviceable, quite a bit of this aircraft carrier is not in working order and we are now on the verge of purchasing this aircraft carrier. Sir, my point is that there is also a talk going on in the armed forces as to whether there is any need at all for an aircraft carrier and, Sir, in modern warfare, with modern planes coming in, the need for an aircraft carrier,